(c) Necessary arrangements have been made with the EEC that the commodities despatched from the European countries must be accompanied by a certificate stating that the consignment is free from radio-active contamination. Similarly, on arrival of commodities in India, arrangements have been made with the Bhabha Atomic Research Centre (BARC) and their environmental laboratories at the port towns in Bombay, Madras and Calcutta for testing of the samples for determination of radio-active residues from the shipments of the commodities received under Operation Flood from the EEC countries. Samples of Skim Milk Powder, butter oil, white butter are being sent to BARC by the IDC for testing and certificates obtained.

लारेंस रोड, नई दिल्ली में पार्क का विकास

2824. **डा० गोविन्द दास रिछारिया :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लारेंस रोड आवासीय क्षेत्र योजना, नई दिल्ली के अन्तर्गत पार्कों के विकास के लिये कितने ट्यूबवैल लगाये गये, यदि ऐसे ट्यूबवैल नहीं लगाये गये है तो उसके क्या कारण है ;

(ख) इस संबंध में मांगे गये टेण्डरों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और इस मामले में विलम्ब के लिये कौन जिम्मेदार है ;

(ग) प्राधिकरण द्वारा पार्कों की मरम्मत व ग्रिल लगाने का काम विशेषकर सी-2 ब्लाक में, अधूरा छोड़ दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस कार्य के कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) इस समय इस क्षेत्र में 3 नलकूप हैं। एक अतिरिक्त नलकूप के लिये निविदायें प्राप्त हो गई हैं जांच प्रक्रियाधीन है। प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति एवं आवश्यक धनराशि प्राप्त होने पर ही यह कार्य दे दिया जायेगा।

(ग) और (घ) जबकि फरवरी, 1986 तक विद्यमान ब्लाक सी-2, लारेंस रोड में पार्कों की मरम्मत और ग्रिल लगने का काम पूरा किया जा चुका है फिर भी दिल्ली विकास प्राधिकरण जहां अपेक्षित होता है, दिन-प्रतिदिन मरम्मत का काम कर रहा है।

लारेंस रोड, नई दिल्ली में लघु सब्जी-मंडी का निर्माण

2825. **डा० गोविन्द दास रिछारिया :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत लारेंस रोड क्षेत्र नई दिल्ली के लिये स्वीकृत लघु सब्जी मंडी और सामुदायिक भवन आदि के निर्माण से संबंधित मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इनके निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में अब तक की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) विपणन केन्द्र और लघु फल और सब्जी बाजार की विस्तृत योजनायें, अन्य आवश्यक सेवाओं और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के ब्यौरों सहित तैयार की जा रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किये जाने की आशा है।

दिल्ली नगर कला आयोग की मंजूरी के पश्चात् ही सामुदायिक केन्द्र की आयो-

जना को भी अन्तिम रूप दिया गया था। तथापि, बाद में संशोधित बृहत योजना में प्रस्तावित एक सामुदायिक केन्द्र के मानदण्डों और मानकों में संशोधन के कारण, विन्यास नक्शे में संशोधन करना पड़ा था और यह प्रगति पर है। संशोधित नक्शे मई, 8 के अन्त तक दिल्ली विकास प्राधिकरण की जांच समिति को प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव है। इसके पश्चात् इसे दिल्ली नगर कला आयोग को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।

Selling of new borns by poverty stricken mothers

2826. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that poverty compelled some women to sell their new born babies recently in league with the hospital staff particularly in Berhampur district of Orissa;

(b) if so, whether such cases of selling their new born babies have also been reported from some other States of the country; and

(c) if so, what remedial steps are being taken to remove such evil practice from the country and what action have been taken against the persons found responsible for committing such crimes?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Children in jails

2827. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of children are in various jails of the country;

(b) if so, what is the estimated number of children who are at present in various jails of the country; and

(c) whether Government propose to get them released from the jails and to put them in various institutions?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) to (c) It is true that in some States children were in jails. The exact number of children in jail presently is not known since in the Conference of State Welfare Ministers and Secretaries incharge of the juvenile justice system held on 21 January, 1987 in New Delhi, it was unanimously agreed that children already in jails will be transferred to institutions set up under the Children's Acts at the earliest. The State Governments are taking action in this regard.

Public sector steel plants

2828. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the number of steel plants working in the public sector upto December, 1986;

(b) how many of these are working with foreign collaboration and how many are being run indigenously; and

(c) what had been the profit/loss accounts of these plants during the last two years?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF MINES IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): (a) Steel Authority of India Limited manages five integrated steel plants in the public sector,